भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 750

बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

750. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बुंदेलखंड देश के सर्वाधिक अल्प विकसित क्षेत्रों में से एक है और इस क्षेत्र के छतरपुर जिले को भी सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सूचीबद्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास अथवा सामान्य रूप से इस क्षेत्र में और विशेष रूप से खजुराहो लोक सभा क्षेत्र में औद्योगिक पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है अथवा योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): जी, हां। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य 26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम विकसित 112 जिलों की उन्नति करना है। यह पांच प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, कृषि एवं जल संसाधन, और आधारभूत अवसंरचना में तेजी से परिवर्तन पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला और उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आकांक्षी जिला कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सभी आकांक्षी जिलों द्वारा की गई प्रगति चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड (http://championsofchange.gov.in/site/coc-home/) पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ख) और (ग): उद्योग की स्थापना करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का विषय है। हालांकि, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के माध्यम से भारत सरकार, उचित नीतिगत कार्यक्रमों के द्वारा देश में समग्र औद्योगिक विकास के लिए सक्षम इकोसिस्टम उपलब्ध कराती है।

I) **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमः** पिछड़े बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवेः** बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वव्यापी विकास के लिए, विशेषकर चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जैसे कम

विकसित जिलों में, राज्य सरकार ने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया है। यह एक्सप्रेस-वे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और यमुना एक्सप्रेस-वे के माध्यम से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ता है और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ii. **बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीआईडीए) :** उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक अवसंरचना के लक्षित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाल ही में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीआईडीए) का गठन किया है। बीआईडीए को स्थायी अवसंरचना के विकास तथा औद्योगिक पार्कों/टाउनशिप के विकास और रखरखाव द्वारा औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देने और राज्य के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिए निवेशक-अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। बीआईडीए का लक्ष्य, निवेश की सुविधा प्रदान करना, नवप्रयोग को बढ़ावा देना, कौशल विकास में वृद्धि करना, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए बुन्देलखंड क्षेत्र में सर्वोत्तम श्रेणी की विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना तथा राज्य के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में योगदान देना है।

iii. **विशेष नीति सहायता:** उत्तर प्रदेश सरकार क्षेत्र में मजबूत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की विभिन्न नीतियों के भाग के रूप में बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए उच्च स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान करती है।

राज्य सरकार की नीति	**बुन्देलखंड के लिए प्रोत्साहन की दरें**	**अन्य क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन दरें**
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार संवर्धन नीति 2022	• स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट • मूल पूंजीगत सब्सिडी का 30% तक • निवल एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के 300% तक	• मध्यांचल तथा पश्चिमांचल में स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट। गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में 50% छूट • मूल पूंजीगत सब्सिडी का 25% तक • निवल एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के 200% तक

iv. **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर:** बुन्देलखण्ड के लिए 4,000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर अनुमोदित किया गया है, जिसमें बिजली निकासी को बढ़ावा देने के लिए पहले 1000 मेगावाट के चरण को वर्ष 2027-28 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

v. **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हस्तशिल्प सेक्टर:** विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित पूरे देश में राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास स्कीम (सीएचसीडीएस) को कार्यान्वित कर रहा है।

II. **मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम:** पिछड़े बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) द्वारा ओरछा जिले के निवारी और **छतरपुर जिले के छतरपुर** क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास।

ii. दिल्ली नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर के तहत विभिन्न भूमि पार्सल की पहचान औद्योगिक नोड्स के रूप में की गई है।

iii. खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के टिकरिया जिले के कटनी में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है।

(घ) : लागू नहीं।

*****